



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 25, 2017/कार्तिक 3, 1939

No. 280]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2017/KARTIKA 3, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)  
सार्वजनिक सूचना  
नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2017  
सं. 35/2015-2020

**विषय:** ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व अवधि में ब्लॉक-वार विस्तार प्राप्त करने संबंधी समयानुवधि में एककालिक छूट।

फा. सं. 18/42/एम-18/पी-5.—विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 2.58 के साथ पठित पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार जनहित में एतद्वारा ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व अवधि में ब्लॉक-वार विस्तार प्राप्त करने से संबंधित प्रक्रियाओं में निम्नलिखित एककालिक छूट प्रदान करते हैं:

1. ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक औसत निर्यात दायित्व कायम रखते समय निर्धारित ब्लॉक अवधि, जैसा लागू हो, के दौरान विशिष्ट निर्यात दायित्व पूरा करते हैं।
2. प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के पैरा 5.14 (ग) में निम्नानुसार उल्लिखित है:

“जहाँ उन मामलों जिसमें ब्लाक से संबंधित निर्यात दायित्व अपूर्ण भाग के अनुपात में बचाई गई शुल्क की राशि पर 2 प्रतिशत संघटन शुल्क के भुगतान के अधीन क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रथम ब्लाक के लिए निर्धारित ईओ का विस्तार किया गया है, को छोड़कर प्रथम ब्लाक के ईओ को उपर्युक्त अनुपात के अनुसार पूरा नहीं किया गया है, प्राधिकार-पत्र धारक ब्लाक के समाप्त होने के तीन महीने के भीतर

प्रथम ब्लाक के कुल अपूर्ण ईओ पर बचाई गई शुल्क की राशि के अनुपात के सीमाशुल्क (राजस्व विभाग द्वारा यथा-अधिसूचित लागू ब्याज सहित) का भुगतान करेगा।”

3. प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के पैरा 5.14 (घ) 1 अप्रैल 2002 और 18.04.2013 के बीच जारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के संबंध में ब्लॉक-वार निर्यात दायित्व हेतु संगत प्रावधानों का अभिशासन विनिर्दिष्ट करता है।
4. संबद्ध प्रावधानों में निर्धारित 3 माह की समय-सीमा, जिसके दौरान ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को संरचना शुल्क का भुगतान कर क्षेत्रीय प्राधिकारी से निर्यात दायित्व अवधि में ब्लॉक-वार विस्तार प्राप्त करना अपेक्षित होता है, को देखते हुए संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी ऐसे अनुरोधों पर विचार करने हेतु असमर्थ होते हैं जिनमें 3 माह के पश्चात् निवेदन किए जाते हैं। कई बार ऐसे अनुरोध पहले किए गए निर्यात के नियमितीकरण हेतु किए जाते हैं। ब्लॉक अवधि का विस्तार प्राप्त करने हेतु निर्धारित समयावधि के भीतर निवेदन न किए जाने संबंधी इस अवधि की छूट हेतु बड़ी संख्या में अनुरोध डीजीएफटी मुख्यालय को प्राप्त होते हैं। इससे ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के समापन में कठिनाई और विलंब हुआ है।
5. ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारकों को संरचना शुल्क का भुगतान कर आवश्यक विस्तार प्राप्त करने हेतु निर्धारित अवधि के भीतर क्षेत्रीय प्राधिकारी से संपर्क करना अपेक्षित था अथवा उनके द्वारा सीमाशुल्क विभाग को ब्लॉक-वार निर्यात दायित्व अवधि को विनियमित करने के प्रयोजन हेतु समानुपाति शुल्क भुगतान किया जाना था। अतः प्रक्रिया में ढील देने के एकमुश्त उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी पहले से किए गए अनुरोधों के लिए ब्लॉक-वार निर्यात दायित्व अवधि के विस्तार के अनुरोधों पर विचार कर सकते हैं परन्तु उस समय-सीमा के बाद के अनुरोधों पर नियमित संरचना शुल्क के भुगतान के अलावा जैसा लागू हो, 5000 रुपये के अतिरिक्त संरचना शुल्क के भुगतान पर विचार किया जा सकता है। इस सुविधा के तहत क्षेत्रीय प्राधिकारी उन अनुरोधों पर भी विचार कर सकता है जो 31.03.2018 तक प्राप्त हुए हैं। यह इस शर्त के अधीन होगा कि मामला अन्यथा ठीक ठाक है और संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आयातित पूँजीगत माल से संबंधित संस्थापन प्रमाणपत्र जमा किया गया है। यह सुविधा 1 सितम्बर, 2004 से जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के लिए है।
6. यह सुविधा निम्नलिखित मामलों के संबंध में उपलब्ध नहीं होगी:
  1. जहाँ मामला क्षेत्रीय प्राधिकारी/सीमाशुल्क प्राधिकारी/अन्य अन्वेषण एजेंसी द्वारा जाँच के अधीन हो/अधिनिर्णीत हो।
  2. जहाँ ईपीसीजी समिति ने विस्तार के ऐसे अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया हो।

### इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व में ब्लॉक-वार विस्तार प्राप्त करने हेतु अनुरोध करने में विलम्ब संबंधी छूट प्रदान करने हेतु एककालिक रियायत प्रदान की जाती है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

**PUBLIC NOTICE****New Delhi, the 25<sup>th</sup>, October, 2017****No. 35/2015-20**

**Subject: Onetime condonation of time period in respect of obtaining block-wise extension in Export Obligation period under EPCG Scheme.**

**F. No. 18/42/AM-18/P-5.**—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.04 read with Paragraph 2.58 of [FTP 2015-20](#), the Director General of Foreign Trade in Public interest hereby makes the following one time relaxations in procedures in respect of obtaining block-wise extension in Export Obligation period under EPCG scheme.

1. The EPCG authorization holders, while maintaining the average export obligation, fulfill the specific export obligation over the prescribed block period as applicable.
2. Para 5.14 (c) of the Handbook of Procedures 2015-2020 states as under:

“Where EO of the first block is not fulfilled in terms of the above proportions, except in cases where the EO prescribed for first block is extended by the Regional Authority subject to payment of composition fee of 2% on duty saved amount proportionate to unfulfilled portion of EO pertaining to the block, the Authorization holder shall, within **3 months** from the expiry of the block, pay duties of customs (along with applicable interest as notified by DOR) proportionate to duty saved amount on total unfulfilled EO of the first block”.
3. The Para 5.14 (d) of the Handbook of Procedures 2015-20 specifies the governance of the relevant provisions for block-wise Export Obligation in respect of EPCG authorizations issued between 1<sup>st</sup> April 2002 and 18.04.2013.
4. In view of the time limit of 3 months prescribed in the relevant provisions, during which time the EPCG authorization holder was required to obtain the block extension in Export obligation from the RA on payment of composition fee, the RAs concerned are unable to consider such requests wherein submissions are made after 3 months. Many times such requests are for regularization of exports already made. A large number of requests for condonation of this period of non-submission within the prescribed time period for obtaining block period extension are received in the DGFT Hqrs. This has caused hardship and delay in closure of EPCG authorizations.
5. The EPCG authorization holders were required to approach RA within the prescribed period for obtaining the requisite extension on payment of composition fee or should have paid the proportionate duty to the Customs to regularize the block-wise EO period. Therefore, as a onetime measure in relaxation of procedure, it has been decided that the RAs concerned may consider the requests for block-wise Export Obligation period extension for the requests already submitted but submitted beyond the time on payment of additional composition fee of Rs. 5000/- in addition to payment of regular composition fee as applicable. The RA may also consider the requests that may be received upto **31.03.2018** under this facility. This shall be subject to the condition that the case is otherwise in order and submission of installation certificate for the capital goods imported to the RA concerned. This facility is for EPCG authorizations issued from 1<sup>st</sup> September, 2004.
6. This facility would not be available in respect of the following cases:

- i. Where the issue is under investigation/adjudicated by RA/customs authority/ any other investigating agency.
- ii. Where the EPCG committee has rejected such extension requests.

Effect of the Public Notice: Onetime relaxation in condonation of delay of submission for obtaining block-wise extension in Export Obligation under EPCG scheme is provided.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade